अल्कोहल एवं प्रोहिबिशन पर एकमात्र हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष-13, अंक-9, मई 2023

आबकारी टाइम्स

केवल सदस्यों हेतु

ड्रग ट्रैफिकिंग में संलग्न लोग हैं मानवता के अपराधी

उत्तर प्रदेश

स्कॉच कम्पनियां करेंगी यूपी में भराई

लाइसेंस नियमों के सरलीकरण से बढ़ा आबकारी राजस्व

आईजीएल में 150 करोड़ से निर्मित परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन

असीमित अवसरों की भूमि है यूपी

दमदार सरकारी नीतियां, डिस्टिलरी उद्योग के लिए बनी गेमचेंजर

हरियाणा

नई आबकारी नीति को मंजूरी

महंगी होगी शराब, सरकार को मिलेगा 10 हजार करोड़

आंध्र प्रदेश

शराब की गुणवत्ता के लिए बनेगी प्रयोगशाला

हिमांचल प्रदेश

आबकारी ने निर्धारित किया 6264 करोड़ रुपए का लक्ष्य

असीमित अवसरों की भूमि है यूपी

दमदार सरकारी नीतियां, डिस्टिलरी उद्योग के लिए बनी गेमचेंजर

उत्तर प्रदेश उद्योग के लिए अब असीमित अवसरों की भूमि बन चुकी है। विशेषकर डिस्टिलरी और **रजनीश अग्रवाल** अल्कोहल क्षेत्र का विस्तार इस प्रकार हुआ है कि वर्तमान सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर सत्र 2022-23 तक सरकार को रिकॉर्ड 300 प्रतिशत अधिक राजस्व का लाभ मिला है। प्रदेश में सबसे अधिक उद्योग अल्कोहल और इसके उपोत्पादों पर आधारित है। अल्कोहल उद्योग का राज्य में सबसे बड़ा औद्योगिक निकाय उत्तर प्रदेश डिस्टिलर्स एसोसिएशन है जिसे यूपीडीए के नाम से जाना जाता है। यूपीडीए के सेक्रेटरी जनरल रजनीश अग्रवाल ने बताया कि राज्य के डिस्टिलरियों की सबसे बड़ी संस्था यूपीडीए है जो पिछले 40 वर्षों से अल्कोहल उद्योग के विकास के लिए कार्य कर रही है। यह संस्था इसके सदस्यों और राज्य एवं केन्द्र सरकार के बीच आने वाली समस्याओं के समाधान में बड़ी भूमिका निभाती है।

उन्होंने बताया कि यूपीडीए दुनिया भर के एडवांस टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस से स्थानीय इंडस्ट्री को परिचित कराने के प्रयास करती रहती है। इस सम्बंध में पिछले साल 22 अगस्त को पहला इंटरनेशनल सेमीनार का आयोजन किया गया था जो ऐतिहासिक साबित हुआ और उसका परिणाम वैश्विक स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिला है। आगामी जुलाई माह में दूसरा दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमीनार 28 और 29 जुलाई को लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है जिसमें ब्राजील, यूएसए, इजराइल सहित कई देशों की टेक्नोलॉजी कंपनियां और स्वदेशी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि ब्राजील की यात्रा पर यूपीडीए और एआईडीए की प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों यात्रा भी की थी। ज्ञातव्य है कि ब्राजील 2जी एथेनॉल की 27 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है।

दूसरा दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमीनार

28-29 जुलाई को लखनऊ में आयोजित कर रही है यूपीडीए

वर्ष 2017 के बाद से सरकार की नीतियां मजबूत और उत्साह जनक रही हैं। पेय मदिरा सेगमेंट में विशेष रूप से कंट्री लिकर की खपत 18 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से 2.3 गुना बढ़ी है। आबकारी विभाग का राजस्व संकलन वर्ष 2017-18 में 17 हजार करोड़ था जो 2022-23 में बढ़कर 41 हजार करोड़ से अधिक हो गया है। राज्य में अब मोलासेस से 285 करोड़ लीटर और ग्रेन से लगभग 62 करोड़ लीटर अल्कोहल उत्पादन की क्षमता हो गई है। अल्कोहल उत्पादन में 150 प्रतिशत की विगत दो सालों में वृद्धि हुई है।

राज्य में बढ़ते आर्थिक निवेश पर श्री अग्रवाल ने बताया कि ग्लोबल इनवेस्ट समिट (जीआईएस) से पहले ही 16392 करोड़ रुपये के निवेश पर 17 एमओयू हुए थे। जीआईएस समिट में हुए एमओयू में से लगभग 2 दर्जन इन्वेस्टर राज्य में बड़ी मात्रा में निवेश करने को तैयार है। सरकार के मुताबिक अधिकतर निवेशकों के लिए जमीन भी उपलब्ध हो गया है। इन निवेशकों में सबसे अधिक निवेश रिन्यूएबल एनर्जी एथेनॉल के लिए होगा। इसके अलावा माल्ट डिस्टिलरी, ग्रेन डिस्टिलरी, डुअल फीड डिस्टिलरी, ईएनए प्लांट और बीयर के लिए निवेश किये जायेंगे।

भारत सरकार के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी) के 2025 तक 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य पर सेक्रेटरी जनरल रजनीश अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान मांग को देखते हुए इसके लिए 1000-1050 करोड़ लीटर अल्कोहल की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि 20 प्रतिशत के लक्ष्य को पाने के लिए कच्चे माल के रूप में ग्रेन प्रमुख स्रोत बनेगा। यूपी में बहुत कम समय में 20 ग्रेन डिस्टिलरी उत्पादन शुरू कर दी है और वर्ष 2024 तक 13 और ग्रेन डिस्टिलरी में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर यूपी में अगले एक साल में 20 से अधिक नई डिस्टिलरी (अनाज + शीरा) में उत्पादन आरम्भ हो सकता है। इस सम्बंध में उन्होंने जानकारी दी कि देश के दूसरे राज्यों के उत्पादकों सहित हम सभी ने ब्रोकेन राइस (टूटा चावल) और डैमेज फूड ग्रेन्स (क्षतिग्रस्त खाद्यान्न) की उपलब्धता पर अपनी मांगे रखी हैं। इसकी कीमत पर भारत सरकार के समक्ष उद्योग की तरफ से हमने प्रस्तुती करते हुए एथेनॉल की प्राइस रिवीजन का भी अनुरोध किया था।

उत्तर प्रदेश में डिस्टिलरी उद्योग के लिए गेम चेंजर के विषय पर उन्होंने बताया कि इसके कई कारक है। शराब उत्पादन का विस्तार, व्यापार को आसान करना, दमदार सरकार की नीतियां और बढ़ता उपभोक्ता आधार राज्य में उद्योग विस्तार के

लिए गेमचेंजर साबित हुए हैं। वर्ष 2018 में प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति घोषित की जिसमें एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक जैसे कि मक्का और जौ को इसमें शामिल किया। लाइसेंस प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और सुबह से शाम तक काम करने का मौका उपलब्ध होना बड़े बदलाव लाये हैं। वर्ष 2017-18 में जहां 63 डिस्टिलरियां 160 करोड़ लीटर अल्कोहल की क्षमता थी वहीं अब 2022-23 में 85 डिस्टिलरियों की क्षमता 348 करोड़ लीटर के आंकड़े छू रहीं हैं। सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी सभी तरह के लाइसेंस और परमिट को आसान कर दिया है। सरकार की पॉलिसी से निवेशकों को प्रोत्साहन मिला जिससे नई डिस्टिलरी की स्थापना और मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ है। इससे आसवनी की क्षमता बढ़ी और स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिली है।

प्रदेश में फार्मा ग्रेड अब्सोल्यूट अल्कोहल की भी अनुमति दे दी गई है। अग्रवाल ने बताया कि फार्मा ग्रेड अल्कोहल के उत्पादन

से देश के बाहर से आयात पर निर्भरता कम होगा। प्रदेश सरकार ने फार्मा ग्रेड अल्कोहल प्लांट स्थापना के लिए भूमि भी आवंटित कर दी है। अब कई कंपनियां इसमें रूचि ले रही हैं। अभी तक यूएसए, आस्ट्रेलिया, चीन आदि देशों से इसका आयात होता है। राज्य में उत्पादन होने पर 10 करोड़ का राजस्व सरकार को इससे प्राप्त होगा।

बड़ी चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए आज यूपी को इस पर गर्व है। अग्रवाल ने बताया प्रदेश सरकार लगातार व्यापार करने में आसानी, सरलीकृत नियामक वातावरण, करों एवं शुल्कों को युक्ति संगत बनाने, बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के साथ बुनियादी ढांचे के विकास और विस्तार में आमूल चूल सुधार किया है। राज्य में पर्यावरण बोर्ड पर्यावरण और उद्योग में सामंजस्य बनाने में मदद कर रही है जिससे उद्योग का विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 520 डिस्टिलरी है जिसमें लगभग 85 अपने उत्तर प्रदेश में हैं और वर्ष 2024 में यहां 21 और डिस्टिलरी आ रही हैं। यूपीडीए का मुख्य उद्देश्य पेय मदिरा के साथ-साथ ग्रेन और एथेनॉल उत्पादन पर आधारित है। यूपीडीए के 16 एक्टिव मेंबर हैं जो राज्य की 90 प्रतिशत ब्राण्डेड पेय मदिरा की आपूर्ति करते हैं।

आईजीएल में 150 करोड़ से निर्मित परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन

ग्लोबल इन्वेस्टर समित 2023 में इंडिया ग्लाईकॉल्स लिमिटेड के चेयरमैन उमाशंकर भारतिया ने बिजनेस हेड एस के शुक्ल के नेतृत्व में 150 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया था, जिसे तय समय में आईजीएल ने पूरा कर लिया। 28 मई को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला जी ने विधि विधान से नव निर्मित 7 मेगावाट पावर इकाई का उद्घाटन किया। मंत्री जी ने कहा की आईजीएल गोरखपुर के इस यूनिट से पूर्वांचल में जहां बिजली उत्पादन बढ़ेगा वहीं दूसरी और एथेनॉल उत्पादन से किसानो की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश पूरी तरह से औद्योगिक हब बन रहा है और अब राज्य के युवाओं को बाहर जाने की जरुरत नहीं होगी उन्हें रोजगार उनके क्षेत्र में ही मिलेगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता आईजीएल के बिजनेस हेड एस के शुक्ल ने किया

और सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। माननीय मंत्री जी को रामजन्मभूमि का प्रतीक भेंट किया। तत्पश्चात आईजीएल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 170 अधिकारियों एवं कर्मचारियों और आईजीएल से जुड़े 20 बिजनेस पार्टनर को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा आज उद्योगों के लिए समय काफी अनुकूल है और आईजीएल के चेयरमैन यू एस भारतिया जी विकास पुरुष हैं जिनके मार्गदर्शन में आईजीएल गोरखपुर काफी प्रगति कर रही है। प्लांट हेड शैलेन्द्र पाण्डेय ने सभी कर्मयोगियों को उनके कार्य हेतु बधाई दी। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन डॉ. सुनील कुमार मिश्र ने किया और सभी के प्रति आभार जताया।